ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Media Bite **11 January, 2021**

Shri Randeep Singh Surjewala, General Secretary, AICC addressed media today.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 3 महीने से देश का 62 करोड़ अन्नदाता किसान और खेत मजदूर आंदोलित है। गांधीवादी और शांतिप्रिय तरीके से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत दिल्ली आ रहे देश के लाखों किसानों को मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने और आदित्यनाथ की सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर पर रोक रखा है। सड़के खुदवा दी गई, वॉटर कैनन और लाठियां और अश्रु गैस चलाए गए। 46 दिन के अंदर 65 किसान कुर्बानी दे चुके हैं । हाड़ कंपकंपाती सर्दी के अंदर बारीश और ओलों के अंदर भूखे – प्यासे किसान न्याय की गुहार लगाते हुए देश की राजधानी के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं और आज देश के उच्चतम न्यायालय, देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई है और वार्ता की विफलता पर निराशा भी जताई है।

हालात ये हो गए हैं इस देश में कि देश की सुप्रीम कोर्ट को सरकार को ये कहना पड़ा कि अगर तुमसे नहीं होता, तो हम कानून स्टे कर देते हैं। इससे बड़ी नाकामी, इससे बड़ी विफलता, इससे बड़ा नाकारापन, इससे ज्यादा जिद्द और अहंकार शायद 73 साल में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा।

मोदी जी अब भी समय है कि जाग जाईए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी, आपकी नाकामी पर मोहर लगा दी, वार्ता की विफलता पर निराशा जता दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए। देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानून खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। देश के किसान की केवल एक मांग है, कोई दूसरी मांग नहीं। **तीनों काले कानून खत्म करिए और प्रधानमंत्री जी, इससे कम देश के किसान को कुछ मंजूर नहीं।**

जब मोदी सरकार खुद कानूनों में 18-18 संशोधन करने को तैयार है, तो साफ है कि ये कानून गलत हैं। अगर ये कानून गलत हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार इनको निरस्त करने, इनको खारिज करने की घोषणा करने से गुरेज क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री जी, क्या पूंजीपतियों के सिक्कों की खनक के आगे इस देश की सरकार का जमीर अब बिक गया है, सवाल ये है?

हम ये मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सामने आएं, अपना नकाब उतारें, अपना राजहठ छोड़ें, पूंजिपतियों का पल्लू छोडें, किसानों का दामन पकड़ें, किसानों के आंसू पोंछे और फौरी तौर से

प्रधानमंत्री आगे आकर इन तीनों काले कानूनों को खारीज करने की घोषणा करें और उसके बाद देश के किसान संगठनों से जो आंदोलनकारी हमारे किसान भाई बैठे हैं, लाखों की संख्या में दिल्ली की सीमा पर, प्रधानमंत्री माफी मांग कर 65 किसानों को श्रद्धांजलि देकर, सीधे उनसे वार्तालाप करें, कानून खत्म करने के बाद, ये हमारी मांग है।

Shri Randeep Singh Surjewala said- India's farmers, 62 crore Annadatas have been agitating now for last 3 months, for over 46 days. Farmers after notifying in a Gandhian manner to come to Delhi, to lodge their protest against the three anti agriculture black laws, have been sitting on Delhi's borders for the BJP Government led by Shri Manohar Lal Khattar and Shri Adityanath at the instance of Home Minister Shri Amit Shah dug up the national highway, lathi charged and used water cannon at the farmers. They have been braving extreme weather, cold weather. They have been braving incessant rain as also hail storms. 65 farmers have sacrificed their lives.

Today even the Supreme Court expressed its anguish and its disappointment over repeated failure of talks and on failure of the Government in being able to find a solution. Never in the 73 years history of this country would a Government like the current one led by Prime Minister Shri Narendra Modi would have been exposed in this fashion for its arrogance, for its intemperate behavior and for its insensitivity towards 62 crore of India's farmers. Mr. Prime Minister, the only thing that is acceptable to the farmers and to agitating farmers and India's farmers, is immediate repeal of the three black laws, nothing short of it is acceptable to India's farmers and nothing short of it will prevail. **So, we call upon the Prime Minister to come forward, to shed the crony capitalists for whom he has enacted these three black laws and to stand with India's farmers to understand their anguish and suffering and to immediately announce repeal of the three black laws.**

Prime Minister should apologize not only to the families of 65 farmers who have sacrificed themselves, but, to 62 crore Annadatas of India and Prime Minister should thereafter speak to the farmers himself, nothing short of it is acceptable to India's Annadatas.

एक प्रश्न पर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो आंदोलन है, वो चल सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सीधे सीधे जिम्मेदारी अगर किसी की है, इस आंदोलन के लिए तो वो श्री अमित शाह, श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री आदित्यनाथ की है। किसान जबरन नहीं आए। क्या किसान को देश की राजधानी में आने का अधिकार नहीं? गांधीवादी तरीके से, पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ये सारे किसान भाई दिल्ली आकर सरकार को अपना विरोध जताना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट, कानून और संविधान की रक्षक है, हम सबका उनमें विश्वास है और अगर

कोई गांधीवादी तरीके से देश की राजधानी में आकर विरोध दर्ज करे, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसका समर्थन करेगी, क्योंकि विरोध प्रकट करना प्रजातंत्र का मूलभूत सिद्धांत है, परंतु सड़कें किसने खुदवाई? अमित शाह जी, मनोहर लाल खट्टर और आदित्यनाथ जी ने! वो बैरियर किसने लगाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने! वहाँ पर बजरी, ईंटे और दूसरे पत्थर किसने फेंके? भारतीय जनता पार्टी की सत्तासीन सरकार ने! पुलिस लगाकर किसानों का रास्ता रोका किसने- भारतीय जनता पार्टी की सत्तासीन सरकार ने, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरुप अमित शाह जी पर, मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला पर और आदित्यनाथ पर, सड़कें रोकने, व्यवसाय का नुकसान करने, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने का सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करना चाहिए।

मोदी जी, अगर ये सारे किसान भाई आकर रामलीला ग्राउंड पर बैठ जाते, या जंतर-मंतर पर बैठ जाते, तो न ट्रैफिक बाधित होता, न किसी को तकलीफ होती, न कोई नुकसान होता, न किसी प्रकार के यातायात में किसी प्रकार की रुकावट होती। तो इसलिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इस बाधा के लिए जिम्मेदार हैं। हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री औऱ गृहमंत्री और दोनों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के इस राष्ट्रविरोधी क़दमों का संज्ञान अवश्य लेगी।

On a question that why do you feel that this fight cannot be sorted out in the Supreme Court and why should the Supreme Court not constitute a committee, Shri Surjewala said- In our democracy, executive is supreme in terms of framing of laws and the Hon'ble High Courts and the Supreme Court are supreme in interpretation and looking at the validity of the laws. First, the Supreme Court has not ordered constitution of any committee so far, so why should I comment upon an order that has not been passed by the Hon'ble Supreme Court as yet.

Secondly, is there a committee higher than the high powered committee constituted by the Government of the Minister's committee? They have already spoken in 8 rounds to the farmers, but, the attitude of the Government is that they will not repeal the black laws. This is not a legal issue; this is not a legalistic issue at all. This is a fight for lives and livelihood. This is a fight for survival of 62 crore farmers. It is not a legal issue. We respect the Hon'ble Supreme Court and its concern for the welfare of the farmers that it has expressed, but, ultimately repeal of the laws and the discretion to repeal the laws, which an autocratic Prime Minister and his Government have made in order to help his crony capitalist friends lies at the doorstep of the Government and not the Supreme Court.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों के मुद्दे पर एक कमेटी बनाए जाने पूछे एक प्रश्न पर श्री सुरजेवाला ने कहा कि ये लड़ाई कानूनी नहीं, ये लड़ाई जिंदगी की लड़ाई है, ये लड़ाई अस्तित्व, रोजी-रोटी की लड़ाई है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं कि उन्होंने किसानों की भीषण समस्या को लेकर

सहानुभूति जताई, परंतु अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई ही नहीं और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं, हम उस पर टिप्पणी क्यों करें? पर एक बात साफ है क्या मंत्रियों की कमेटी से बड़ी भी इस देश में बड़ी कमेटी कोई हो सकती है वार्तालाप के लिए? देश के कृषि मंत्री और देश के दूसरे मंत्रियों के समूह ने जो वार्तालाप की वो कमेटी ही तो है, पर सरकार बेईमान है, मोदी सरकार की मंशा में साजिश और षड़यंत्र है और इसलिए वो इन तीन काले कानून खत्म करने को तैयार नहीं। ये लड़ाई कानूनी नहीं, ये किसान जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है और जिंदगी और अस्तित्व की लड़ाई का निर्णय तब होगा, जब प्रधानमंत्री देश से माफी मांग कर इन तीन काले कानूनों के खात्मे का निर्णय करेंगे और खुद आगे आकर किसानों से बात करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाने के संदर्भ में पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस प्रकार से निराशा जाहिर की, वार्ता की विफलता को लेकर, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी एक तरह से अपने आपको इस वार्ता की विफलता और किसानों की निराशा और किसानों की तकलीफ को वो भी महसूस कर रहे हैं। पर मुझे ये बताईए क्या सरकार ने पहले से ही एक कमेटी नहीं बना रखी और देश के कृषि मंत्री उस कमेटी के सदस्य हैं, देश के मंत्रीगण का समूह और सबसे बड़े अधिकारी उस कमेटी के सदस्य हैं। सवाल कमेटी बनाने का नहीं, सवाल मोदी सरकार की बेईमानी का है। सवाल मोदी सरकार की मंशा और षड़यंत्र का है, जो तीनों काले कानून खत्म ही नहीं करना चाहती। इसलिए देश का किसान कानूनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो तो बॉर्डर पर बैठा है, वो तो मोदी सरकार से लोहा ले रहा है, क्योंकि उसके लिए ये लड़ाई कानूनी नहीं, उसके लिए ये लड़ाई रोजी-रोटी, अस्तित्व और जिंदगी की है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई इस अहंकारी सरकार से लड़ रहा है, जिसने पूंजीपतियों के आगे घुटने टेक रखे हैं।

On another question that the BJP which is having 700 press conferences, 700 *Chaupals*, mega rallies by the Chief Ministers in its process to outreach farmers and explain them good clauses in these laws, Shri Surjewala said- The fraudulent acts of BJP and its leaders attempting to dupe and deceive India's farmers will not work. India's 62 crore farmers, irrespective of region, religion, caste or creed have come together to fight for their survival. It is not a Congress Vs BJP fight. It is not a Press Conference oriented fight, it is a livelihood fight. Prime Minister Modi and BJP Government are snatching away the lives and livelihoods of the farmers. That's why we say constantly, it is neither a legalistic issue, nor a constitutional issue. The issue is even bigger than that and that is the issue of survival of the farming sector per se and the lives and livelihoods of the farmers and these fraudulent press conferences in order to dupe and deceive and to create an atmosphere through media will not work at all. For on the ground, farmer has understood that this Government is subservient to the handful of crony capitalists and wants to sell off the 25 lakh crore agri- commodities trade to 4 or 5 people, so that then they can

dupe and deceive all 130 crore people of this country at their whims and fancy.

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पहली महापंचायत का कैमला गांव, करनाल (हरियाणा) में क्या हाल हुआ, ये आपके चैनल ने भी दिखाया।सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों से धोखा और षड़यंत्र करने की कितनी भी साजिश करे, देश का किसान गरीब और खेत, मजदूर ये जान गया है कि सिक्कों की खनक के आगे मोदी सरकार ने अपना सर्वस्व बेच डाला है और वो खेत, खलिहान और रोजी-रोटी को चंद पूंजीपतियों को बेचना चाहती है और किसान, मजदूर और गरीब कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए भाजपा का ये मिथ्या प्रचार और षड़यंत्रकारी व्यवहार चलने वाला नहीं, इसका यही हश्र होगा, जो कल दुर्भाग्य से श्री मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत का हुआ है।

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC